बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 132 ● नई दिल्ली ● शनिवार 07 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर कूदी महिला, सीआरपीएफ ने बचाई जान; पीक आवर में मेट्रो सेवा रही बाधित

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां स्थित ब्लू लाइन पर एक महिला ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला के कूदते ही प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ शोर और अफरा-तफरी का माहौल छा गया। इसके बाद आनन-फानन में सीआरपीएफ के जवानों ने महिला को ट्रैक से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए ब्लू लाइन पर मेट्रो की सेवाएं भी प्रभावित हुईं। इससे दफ्तर, कॉलेज आदि जाने वाले लोगों को सुबह-सुबह परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में लेट भी हो गए। कई लोगों ने जहां मेट्रो के आने का वेट किया, वहीं कई लोग मेट्रो छोड़ अपने साधनों से अपनी मंजिल तक पहुंचे।

दिल्ली मेट्रो की पहली रिंग पूरी, मैजेंटा लाइन का विस्तार; पीएम मोदी 8 मार्च को करेंगे उद्घाटन-शिलान्यास

नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आठ मार्च को मेट्रो के दो कॉरिडोर चालू हो जाएंगे। इसमें से एक कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिलेगी। वहीं, तीन अन्य कॉरिडोर की नींव भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रोजेक्टों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनके पूरा होने के बाद दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को विस्तार मिलेगा। आवाजाही निर्बाध होने से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी। इससे आबोहवा भी साफ होगी इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने पिंक लाइन पर मजलिस पार्कद्धमौजपुर और मैजेंटा लाइन पर दीपाली चौकद्धमजलिस पार्क सेक्शन पर मेट्रो संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रायल रन के बाद कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) ने यात्रियों के लिए संचालन की मंजूरी दे रखी है। वहीं, दिल्ली मेट्रो के फेज-पांच (ए) के तहत तीन नए कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास भी होना है। इन मेट्रो परियोजनाओं की कुल लागत 18,300 करोड़ रुपये से अधिक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए निरंकारी मंडल के सामने डीडीए उत्सव स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह प्रोजेक्ट राजधानी को सही मायनों में विकसित दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

दिल्ली की पहली रिंग मेट्रो पूरी, पूर्वी दिल्ली को बड़ी राहत

मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर सेक्शन की लंबाई 12.3 किलोमीटर है। इसके 8 एलिवेटेड स्टेशन हैं। यह कॉरिडोर पहले से चालू मजलिस पार्क-शिव विहार पिंक लाइन का हिस्सा है। नया कॉरिडोर शुरू होने से दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिलेगी। पिंक लाइन का पूरा कॉरिडोर करीब 71.56 किलोमीटर होगी। इस पर मेट्रो चलने से मजलिस पार्क, बुराड़ी, झड़ौदा माजरा, जगतपुर-वजीराबाद, सूरघाट, नानकसर-सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर-बाबरपुर जैसे इलाके सीधे मेट्रो से जुड़ जाएंगे।

मैजेंटा का हिस्सा भी पूरा, नोएडा तक मिलेगी राहत

दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक का कॉरिडोर मैजेंटा लाइन का हिस्सा है। इसकी लंबाई 9.92 किलोमीटर है। इसमें 7 एलिवेटेड स्टेशन हैं। यह कॉरिडोर पहले से संचालित बोटेनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन मैजेंटा लाइन का विस्तार है। इसके जुड़ने से मैजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर हो जाएगी। इसके चालू होने से दीपाली चौक, मधुबन चौक, उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार, हैदरपुर गांव, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क पहुंचना आसान होगा।

महत्वपूर्ण रहा यह प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह कॉरिडोर इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी अहम है। दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर का एक हिस्सा लगभग 28.36 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। यह दिल्ली मेट्रो के एलिवेटेड सेक्शनों में सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है। वहीं, मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर के निर्माण में यमुना नदी पर एक नए पुल का निर्माण करना पड़ा और डबल-डेकर वायडक्ट तैयार किया गया। यह दिल्ली मेट्रो का यमुना नदी पर पांचवां पुल है।

फेज-पांच (ए) के तहत तीन कॉरिडोर का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के फेज-पांच (ए) के अंतर्गत तीन नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। इनमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर, एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक गोल्डन लाइन विस्तार और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन विस्तार शामिल हैं। रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर की लंबाई 9.913 किलोमीटर होगी और यह भूमिगत बनाया जाएगा। इसमें नौ नए स्टेशन होंगे जिनमें आरके आश्रम मार्ग (निर्माणाधीन), शिवाजी स्टेडियम, युगे-युगेन भारत, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ स्टेशन शामिल हैं। यह कॉरिडोर कर्तव्य भवनों, भारत मंडपम और युगे-युगेन भारत संग्रहालय जैसे प्रमुख स्थलों को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दूसरी तरफ एरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक गोल्डन लाइन विस्तार की लंबाई 2.263 किलोमीटर होगी और यह भूमिगत बनाया जाएगा। इसमें एक नया स्टेशन होगा और दोनों पहले से संचालित स्टेशनों को आपस में जोड़ा जाएगा। तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन विस्तार की लंबाई 3.9 किलोमीटर होगी और यह एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। इसमें सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज स्टेशन शामिल होंगे।

नोएडा-फरीदाबाद को भी मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से एनसीआर के शहरों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के निवासी वायलेट लाइन के माध्यम से तुगलकाबाद पहुंचकर गोल्डन लाइन के जरिए सीधे एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल-1 तक जा सकेंगे। वहीं, नोएडा के यात्री मैजेंटा लाइन से कालिंदी कुंज पहुंचकर गोल्डन लाइन के माध्यम से एयरपोर्ट और दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों तक आसानी से यात्रा कर सकेंगे।

फांसी घर विवाद- विधानसभा समिति के सामने पेश हुए केजरीवाल, बोले- भाजपा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा से जुड़े फांसी घर मामले में अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली विधानसभा का जो परिसर है ये ऐतिहासिक इमारत है। अंग्रेजों के जमाने में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी तो उस समय ये इमारत बनाई गई थी। 1912 में ये इमारत बनाई गई थी। इस इमारत में 2022 में तत्कालीन स्पीकर राम निवास गोयल से पता चला कि इस इमारत के एक कोने में एक फांसी घर था। उस फांसी घर में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। गोयल साहब ने मुझे बुलाया था और कहा था कि इस जगह को पर्यटक के लिए खोलना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सके। हमने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई है वो लोग साबित करने में लगे हुए हैं वो फांसी घर नहीं थी बल्कि टिफिन रूम था। केजरीवाल ने आगे कहा, मैं समझता हूं स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। आज मेरे को

विधानसभा बुलाया गया था कि साबित करो वो फांसी घर था। मैंने कहा कि स्पीकर साहब ने सारी जांच करने के बाद किया था लेकिन आप बताए कि आपके पास क्या सबूत है कि वो टिफिन घर था। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब ये जानबूझकर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए उसे फांसी घर नहीं था और टिफिन घर साबित करने में लगे हुए हैं। जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है तब से दिल्ली का हाल बुरा है। इनको सिर्फ राजनीति करना है, दिल्ली से मतलब नहीं है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल को पत्र लिखकर इस अस्वीकृति की जानकारी दी। पत्र के अनुसार, विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है। प्रक्रिया के नियम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं देते हैं। विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है।

आतिशी का भाजपा पर हमला

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा ने फांसी घर के मुद्दे के मामले में बुलाया है। मैं आज भाजपा से पूछना चाहती हूं कि क्या यह दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है? भाजपा वायु प्रदूषण या सड़कों के मामले पर चर्चा के लिए किसी को नहीं बुला रही है।

आज न तो विधायक और न ही मीडिया को विधानसभा के अंदर जाने दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि उन्हें (भाजपा) कितना डर है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में विधानसभा के एक कमरे को फांसी घर बताकर संरक्षित किया था। जिसका उद्घाटन तत्कालीन अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 9 अगस्त 2022 को किया। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने पिछली सरकार के इस पूरे काम को खारिज कर दिया और इस रूम को टिफिन रूम करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप पर दिल्लीवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जांच कराने का एलान किया था।

सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा पहुंचे ईरान कल्चर हाउस , खामेनेई के निधन पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित ईरान कल्चर हाउस पहुंचा और भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा भी उपस्थित थे। उन्होंने ईरानी प्रतिनिधि से बातचीत के दौरान अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और सहानुभूति जताई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने गुरुवार को ईरानी दूतावास में भारतीय सरकार की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब नई दिल्ली ने खामेनेई की हत्या पर प्रत्यक्ष बयान जारी नहीं किया। इसके बजाय, सरकार ने अपने उस पुराने रुख को दोहराया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए।

यूएस ने दी रूसी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट - कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश बोले- कब तक चलेगा ये ब्लैकमेल

नई दिल्ली । कांग्रेस ने अमेरिकी फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अमेरिका की ओर से भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए। पार्टी ने पूछा कि आखिर यह अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक चलता रहेगा। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक कवितानुमा पोस्ट में कहा कि ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा, पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा, यह अमेरिकी ब्लैकमेल। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी भारत की मौजूदा विदेश नीति की आलोचना की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति देश की जनता की सामूहिक इच्छा से तय होनी चाहिए। उनके अनुसार यह नीति देश के इतिहास, भूगोल और सत्य व अहिंसा जैसे आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हम आज देख रहे हैं वह कोई नीति नहीं है, बल्कि एक समझौता किए हुए व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

खड़गे ने भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति के कारण भारत लगातार कूटनीतिक क्षेत्र में अपनी जगह छोड़ता जा रहा है। ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच, अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर 30-दिवसीय अस्थायी छूट जारी करने की घोषणा की है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेस्सेंट ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प की ऊर्जा नीति के कारण तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह बनाए रखने के लिए, ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी 30-दिवसीय छूट जारी कर रहा है। बेस्सेंट ने स्पष्ट किया कि यह जानबूझकर अल्पकालिक उपाय रूसी सरकार को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह केवल उन तेल के लेन-देन को अधिकृत करता है, जो पहले से ही समुद्र में फंसे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है, और वाशिंगटन को उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा। यह ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया था। उस समय प्रशासन का तर्क था कि दिल्ली की खरीद रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा दे रही थी। पिछले महीने, अमेरिका और भारत ने व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक ढांचे पर पहुंचने की घोषणा की थी। इसके बाद, ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगे 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटा दिया था, जिसमें नई दिल्ली की मॉस्को से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया था।

कृपया इस्तीफा दे दीजिए लेकिन ट्रंप के सामने झुकिए मत अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान

नई दिल्ली । मिडिल ईस्ट में इन दिनों काफी अफरा-तफरी मची हुई है. इस बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका का मूड बदल गया है. अमेरिका लंबे समय से रूस से तेल की खरीद रोकने को लेकर भारत पर दबाव बनाता रहा है. हालांकि, अब उसी अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों का वक्त और दिया है. इस मुद्दे को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है. विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर, कृपया इस्तीफा दे दीजिए पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए. सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है. अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में मोदी सरकार पर निशाना साधा है. इस बीच उन्होंने लिखा कि भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? उन्होंने आगे लिखा कि पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक, हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई. अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी आखिर आपको ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस की वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं. भारत हजारों वर्ष पुराना देश है. भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश

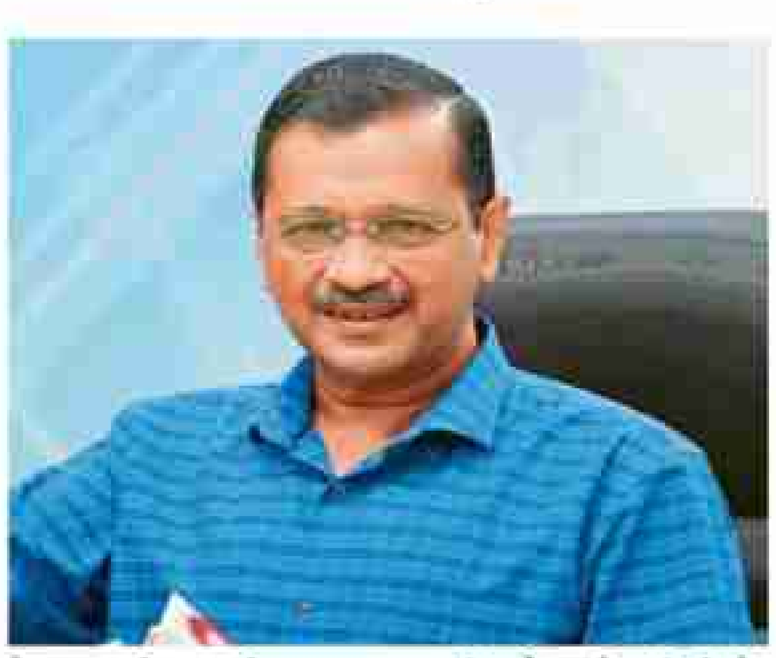

है. भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किये हैं. आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया. आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा.

आप नेता संजय सिंह ने बोला हमला

आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपने भारत का स्वाभिमान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है. देश को मालूम है आप एप्सटीन फाइल्स में बुरी तरह फंस चुके हैं. आपका दोस्त अडानी यूएस में भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है उन्होंने आगे कहा कि अब आपको रूस से तेल खरीदने के लिए भी ट्रंप की अनुमति चाहिए. संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को इतना कायर और कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए आप स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दो.

रायसभा की ओर नीतीश कुमार- बिहार से दिल्ली तक बदलते शक्ति संतुलन का संकेत

बिहार की राजनीति में यदि किसी एक नेता ने लंबे समय तक सत्ता और व्यवस्था की धुरी को नियंत्रित किया है, तो वह हैं नीतीश कुमार। वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने न केवल प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया, बल्कि राजनीतिक विमर्श की दिशा भी बदली। अब उनका रायसभा की ओर प्रस्थान केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति तक व्यापक प्रभाव डालने वाला कदम माना जा रहा है। 5 मार्च को नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि यह निर्णय व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सुविचारित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक मंचों पर उनके भाषणों और राजनीतिक सक्रियता को लेकर यह चर्चा भी होती रही है कि समय का प्रभाव अब उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगा है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, तो समर्थकों ने इसे अनुभव की परिपक्वता बताया। किंतु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने राज्य की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर बदला। कानून-व्यवस्था में सुधार और शराबबंदी जैसे कठोर निर्णयों ने उन्हें एक निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। लालू प्रसाद के शासनकाल के बाद बिहार को विकास की नई धुरी पर खड़ा करने का श्रेय बड़े पैमाने पर उन्हें दिया जाता है। उनका कार्यकाल आने वाले दशकों तक राजनीतिक अध्ययन का विषय बना रहेगा। रायसभा की ओर यह कदम बिहार की सत्ता संरचना में परिवर्तन का संकेत भी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी बड़े सहयोगी के रूप में अधिक निर्णायक भूमिका में उभरेगी। इससे जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल के बीच भविष्य में किसी प्रकार की समीपता की संभावनाएं लगभग समाप्त होती दिखाई देती हैं। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर मजबूती और एकजुटता का संदेश भी देता है, विशेषकर ऐसे समय में जब विपक्ष गठबंधन की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगाता रहा है। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति से संबंध पुराना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उन्होंने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला। वे कई अवसरों पर गैर-कांग्रेसी राजनीति के संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी चर्चा में रहे। एक समय ऐसा भी प्रतीत हुआ कि यदि राजनीतिक समीकरण अनुकूल हुए तो वे राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। किंतु गठबंधन की जटिलताओं और संख्याबल की वास्तविकताओं ने उस संभावना को मूर्त रूप नहीं लेने दिया। अब रायसभा जाने के साथ राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि उन्हें केंद्र में और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उप-प्रधानमंत्री पद को लेकर अटकलें भी सामने आ रही हैं। यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरण, विशेषकर पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच, को और सुदृढ़ कर सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इसका प्रभाव आगामी चुनावों तक देखा जा सकता है। अनुभवी प्रशासक और संतुलित वक्ता के रूप में वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख प्रचारक बन सकते हैं।हालांकि इस रणनीति के भीतर जनता दल (यूनाइटेड) के भविष्य को लेकर भी प्रश्न मौजूद हैं। यदि पार्टी में समय रहते युवा नेतृत्व को आगे नहीं लाया गया, तो उसकी पहचान केवल सहयोगी दल तक सीमित हो सकती है। यह भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ने ही जदयू को दीर्घकालिक सत्ता का आधार दिया है। ऐसे में रायसभा की ओर यह कदम राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए नई भूमिका ग्रहण करने जैसा है। समग्र रूप से देखें तो नीतीश कुमार का रायसभा जाना एक युगांतकारी मोड़ का संकेत है। इससे उनका राष्ट्रीय हस्तक्षेप पुनः बढ़ सकता है और केंद्र की सत्ता संरचना में उनकी भूमिका अधिक स्पष्ट हो सकती है। किंतु बिहार की राजनीति में फिर से नीतीश का जो भावनात्मक नारा कभी जनसभा की पहचान हुआ करता था, वह अब धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज होता दिखाई देता है। राजनीति में समय का चक्र निरंतर चलता है–नेतृत्व बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, परंतु इतिहास में दर्ज कार्य और निर्णय ही किसी नेता की वास्तविक पहचान बनते हैं।

पुलिस और जनता : विश्वास का खोया हुआ सिद्धांत

1934 में, जब पंजाब में कानून प्रवर्तन के कामकाज को संचालित करने वाले पुलिस नियम बनाए गए थे, तब प्रशासकों ने एक ऐसा आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किया था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत का आपराधिक कानून और उस पर आधारित पुलिस संगठन एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर टिके हैं-सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना कानून के दायरे में समुदाय के प्रत्येक सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस और मैजिस्ट्रेट प्रणाली अलग-थलग अधिकार के साधन के रूप में नहीं, बल्कि इस साझा जिम्मेदारी को सहायता, उसे लागू करने और मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई संस्थाओं के रूप में मौजूद हैं।

पुलिस और जनता के बीच के इस रिश्ते को व्यवस्था की रीढ़ माना गया था। नियमों ने आगे एक ऐसा आदर्श स्थापित किया, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को हर कानून का पालन करने वाले नागरिक द्वारा एक 'बुद्धिमान और निष्पक्ष मित्र' और जीवन व संपत्ति के रक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि जनता पुलिस को एक मित्र और रक्षक के रूप में देखती है, तो नागरिक जांच में सहायता करेंगे, अपराधों की तुरंत रिपोर्ट करेंगे और शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे। जब पुलिस और लोगों के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो अपराध होने से पहले ही रुक जाते हैं क्योंकि समुदाय सतर्क और जिम्मेदार बन जाता है। लेकिन जब वह विश्वास खत्म हो जाता है, तो लोग अक्सर चुप्पी साध लेते हैं, अपराधियों के साथ समझौता कर लेते हैं या निजी तौर पर मामले सुलझाने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में, पुलिस अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के अपने प्रयासों में अलग-थलग पड़ जाती है और सफलता सीमित हो जाती है। मुझे 39 वर्षों तक पंजाब पुलिस में सेवा करने का सौभाग्य मिला। मेरा करियर पंजाब के आधुनिक इतिहास के सबसे अशांत दौर में रहा-उग्रवाद के उदय से लेकर उसकी अंतिम हार तक। मैं उन कठिन वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाओं का हिस्सा रहा और मैंने पुलिस बल द्वारा दिखाए गए साहस, बलिदान और चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मुझे एक ऐतिहासिक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने का सम्मान मिला, जिसमें अस्सी हजार से अधिक नागरिक शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की शपथ लेने के लिए एकत्र हुए थे। वह क्षण मेरे करियर के सबसे प्रेरक अनुभवों में से एक है। इसने साबित किया कि जब पुलिस और जनता आपसी विश्वास के साथ एक साथ खड़े होते हैं, तो उग्रहिंसा के सबसे काले दौर पर भी विजय पाई जा सकती है। हालांकि, यह देखना उतना ही कष्टकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में विश्वास की वह भावना धीरे-धीरे कमजोर हुई है। सबसे परेशान करने वाले घटनाक्रमों में से एक, पुलिस प्रणाली के भीतर पेशेवर गरिमा का क्षरण होना है। पहले के समय में, अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को महत्व देते थे। नियुक्तियों को जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था।

आज, दुर्भाग्य से, यह धारणा बढ़ रही है कि कुछ अधिकारी अनुकूल नियुक्तियों या पदों के लिए अपने आत्म-सम्मान का सौदा करते हैं। जब पेशेवर ईमानदारी से समझौता किया जाता है तो पुलिसिंग का पूरा ढांचा कमजोर होने लगता है। इससे भी अधिक दुःखचताजनक कुछ राजनीतिक वर्गों, आपराधिक नेटवर्क और प्रशासन के भीतर के तत्वों के बीच एक कथित गठजोड़ का उभरना है। जब ऐसे गठबंधन जड़ जमा लेते हैं, तो कानून के शासन को गंभीर क्षति पहुंचती है। आज पंजाब संगठित अपराध, नशा तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई क्षेत्रों में, ये तत्व खतरनाक आत्मविश्वास के साथ काम करते दिखाई देते हैं। जबरन वसूली, गिरोह दुःखहसा और सीमा पार तस्करी की घटनाओं ने आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। जब ऐसी धारणा फैलती है, तो यह पुलिस की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है और राज्य में जनता के विश्वास को कम करती है। एक और चिंताजनक प्रवृत्ति उन सेवाओं का बढ़ता नौकरशाहीकरण है, जो कभी पुलिस नेतृत्व के विवेकाधीन अधिकार का हिस्सा थीं। सत्यापन सेवाएं और अन्य नियमित प्रक्रियाओं को तेजी से सुविधा केंद्रों जैसे केंद्रीकृत सेवा केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि इन केंद्रों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना था लेकिन वे अक्सर पुलिसिंग को एक यांत्रिक लेनदेन तक सीमित कर देते हैं। पुलिसिंग को कागजी कार्रवाई और फीस तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह मूल रूप से राज्य और नागरिक के बीच का एक रिश्ता है। जब मानवीय तत्व गायब हो जाता है और सब कुछ प्रक्रियात्मक हो जाता है, तो पुलिसिंग की भावना फीकी पड़ने लगती है। चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल बेहतर तकनीक या सख्त कानूनों की आवश्यकता है, बल्कि उस मौलिक सिद्धांत को पुनर्जीवित करने की भी, जिस पर पुलिसिंग का निर्माण हुआ था-पुलिस और लोगों के बीच विश्वास। अधिकारियों को सुलभ, शिकायतें सुनने में धैर्यवान और कानून लागू करने में दृढ़ होना चाहिए। पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कदाचार और भ्रष्टाचार की तुरंत जांच हो, साथ ही ईमानदार अधिकारियों के मनोबल और गरिमा की रक्षा भी की जाए। पंजाब के पुलिस बल का साहस और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। उनके बलिदानों को हमें बल के भीतर व्यावसायिकता और ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बहाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। (पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार)- इकबाल सिंह लालपुरा।

सम्पादकीय...

विकसित भारत के सपने में हकीकत के रंग भरता 'गुजरात'

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस धरती पर विकसित भारत का जो ख्वाब स्वयं देखा और समस्त देशवासियों को दिखाया, आज उसी धरती जैसा विकास का रंग पूरे भारत की सरजमीं पर नजर आ रहा है। विकसित भारत का एक खूबसूरत उदाहरण है, 'गुजरात'। गुजरात की धरती सिर्फ उद्योग, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन, डेयरी आदि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास का ही नाम नहीं है, बल्कि इस विकास की गति में इस राज्य ने अपनी विरासत और संस्कारों का दामन कसकर थामे रखा है। यह राज्य इस बात का गवाह है कि जो ख्वाब व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर लोक हित के लिए देखे जाते हैं, वे निश्चित रूप से साकार होते हैं। इसका एक उदाहरण गुजरात के एकता नगर का 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर सरदार पटेल जी द्वारा पहनी गई जैकेट के दूसरे और तीसरे बटन के बीच बनी जगह में खड़े होकर जब कोई व्यक्ति बाहर की ओर देखता है, तो पहली नजर में उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है। यह सपना 'सरदार सरोवर बांध' का था। उनकी दूरदृष्टि आज केवल 'गुजरात की जीवन-रेखा' ही नहीं, बल्कि इस बांध का कई पड़ोसी राज्यों को भी फायदा हो रहा है। सरदार सरोवर बांध का पानी गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लगभग 18 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करता है। यह हजारों गांवों और कई शहरी केंद्रों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति करता है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1,450 मैगावाट है, जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में समान रूप से साझी की जाती है। सरदार सरोवर बांध के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित कई पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो इस इलाके को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 375 एकड़ में फैला सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, फूलों की घाटी, आरोग्य वन, मियावाकी वन, कैक्टस गार्डन और एकता वल्ड जैसे करीब 27 से अधिक मनोहारी पर्यटन स्थल हैं, जो यहां पर्यटकों को 2-3 दिन ठहरने के लिए विवश कर देते हैं। इन पर्यटन स्थलों में केवल स्थानीय निवासियों को ही रोजगार दिया गया है। यहां ऑटो चालक केवल महिलाएं ही हैं। अहमदाबाद में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अपने आप में विकसित परिवहन प्रणाली की एक झलक प्रस्तुत करती है। लगभग 508 किलोमीटर लंबी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना विकसित भारत की उस तस्वीर का प्रतिबिंब है, जहां आने वाले कुछ वर्षों में ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। निस्संदेह गुजरात का विकास बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ रहा है लेकिन साथ ही यह राज्य अपनी 4500 साल पुरानी विरासत को भी संभाल रहा है। अहमदाबाद से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर, 'लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर' के दर्शन होते हैं। यह बंदरगाह एक नदी के तट पर बनाया गया था, जो समुद्र से जुड़ती थी, जिससे व्यापार और परिवहन सुगम हो जाता था। यह स्थान प्राचीन भारतीय इतिहास में व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास का प्रतीक है। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर परियोजना द्रुत गति से प्रगति कर रही है।

आखिरकार हिन्द महासागर आ पहुंची अमेरिकी दादागिरी- मेहमान की रक्षा न कर पाने के बाद क्या भारत चेतेगा ?

आलोक बाजपेयी

अमेरिका ने एकतरफा दादागिरी और उसकी वैश्विक पहुँच का प्रदर्शन करने के लिए 4 मार्च 2026 को हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS Dena को अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी से डुबो दिया। यह हमला टॉरपीडो से हुआ और घटना का ऐतिहासिक महत्व समझे बताते हुए अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पुष्टि की है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन देश के जहाज को टॉरपीडो से डुबोने की यह पहली घटना है। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट - गाले से लगभग 40 समुद्री मील (75 किमी) दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ। यह क्षेत्र भारतीय समुद्री सीमा के निकट हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है। IRIS Dena एक मौज-श्रेणी का गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट था। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता, चेतावनी और शर्मिंदगी का विषय यह है कि यह जहाज हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित भारत के MILAN 2026 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेकर वापस लौट रहा था। जहाज पर चालक दल के लगभग 180 सदस्य सवार थे। इसमें 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है। अब तक 32 घायल नाविकों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा बचाया गया है और उन्हें गाले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और श्रीलंका की नौसेना तथा वायुसेना बचाव अभियान चला रही है। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर भारी तनाव पैदा कर दिया है और भारत के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखें तो हिंद महासागर, जो अब तक व्यापार के लिए तुलनात्मक रूप से शांत था, अब एक वॉर जोन की तरह देखा जा रहा है। भारत के इतने करीब ऐसी घटना होने से समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान ने इसेकायराना हमला बताया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जवाबी कार्रवाई के रूप में हॉर्मुज जलडमरूमध्य को और सख्ती से बंद कर सकता है, जहाँ से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार होता है। भारत के लिए यह स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ अमेरिका के साथ गहरे रक्षा संबंध हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रणनीतिक रिश्ते (जैसे चाबहार पोर्ट)। भारत ने शांति की अपील की है, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल और व्यापार मार्ग में रुकावट भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकती है। इस हमले की खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका भी है जिसका असर भारत के व्यापार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है? भारत पर इसके प्रभाव कई स्तरों पर पड़ सकते हैं–रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। IRIS Dena के डूबने की घटना भारतीय समुद्री सीमा के भीतर नहीं, बल्कि उसके निकट अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई है। इसका सटीक स्थान श्रीलंका के दक्षिणी शहर गाले के तट से लगभग 40 समुद्री मील (करीब 74-75 किमी) दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ। यह स्थान भारत के सबसे दक्षिणी छोर (कन्याकुमारी) से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व की दिशा में है। यह भारत की मुख्य प्रादेशिक समुद्री सीमा तट से बाहर है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (200 समुद्री मील) के भीतर नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि यह भारत केप्राथमिक समुद्री पिछले हिस्से में एक बड़ा सैन्य हस्तक्षेप है। भले ही यह घटना तकनीकी रूप से भारतीय सीमा में नहीं हुई, लेकिन यह भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह जहाज विशाखापत्तनम में भारत के MILAN 2026 अभ्यास से लौट रहा था। यह हमला उन प्रमुख व्यापारिक रास्तों के पास हुआ है जहाँ से भारत का अधिकांश तेल और मालवाहक जहाज गुजरते हैं। इसे भारत के लिए बेइज्जती का मामला न भी मानें तो एक गंभीर रणनीतिक चिंता और कूटनीतिक चुनौती का विषय है। इस घटना ने भारत के लिए कूटनीतिक रूप से असहज स्थिति जरूर उत्पन्न कर दी है। भारत खुद को हिंद महासागर का Net Security Provider मानता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का अर्थ है, किसी क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली मुख्य शक्ति, जो अपनी और अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करती है। भू-राजनीति में यह भारत जैसे राष्ट्रों को संदर्भित करता है जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने भारत के दरवाजे पर आकर एक युद्धपोत डुबो दिया, और भारत इसे रोक नहीं पाया। यह भारत की निगरानी और निरोधक क्षमता के लिए चिंता का विषय है। यह भारत के अतिथि पर हमला है क्योंकि IRIS Dena भारत के निमंत्रण पर MILAN 2026 अभ्यास में आया था। इसका उद्देश्यमहासागरों के माध्यम से एकता था। किसी देश के मेहमान जहाज को उसके घर लौटते वक्त निशाना बनाना, भारत की मेजबानी और क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। भले ही कहें कि इस हमले का लक्ष्य ईरान था, भारत नहीं, जैसा कि पेंटागन ने कहा है अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान की नौसेना को खत्म करना था।

यह हमला भारत के खिलाफ नहीं था, लेकिन यह भारत केरणनीतिक बैकयार्ड में हुआ, जो भारत की संप्रभुता का अपमान भले न हो, लेकिन उसकी समुद्री सुरक्षा के दावे को चुनौती देता है। यह सीधे-सीधे भारत की समुद्री डोमेन अवेयरनेस और निगरानी क्षमता पर प्रश्नचिह्न है। अब तक पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत से दूर था, लेकिन इस हमले ने हिंद महासागर को भी एक युद्ध क्षेत्र War Zone बना दिया है। अमेरिका का संदेश स्पष्ट है अमेरिका ने यह हमला करके दिखाया है कि जब बात उसके दुश्मन (ईरान) की हो, तो वह भारत जैसी मित्र शक्ति केक्षेत्रीय प्रभाव या कूटनीतिक संवेदनशीलता की परवाह नहीं करेगा। भारत के लिए एक स्पष्ट चेतावनी वाकेक-अप कॉल है। यह भारत को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हिंद महासागर में उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी वह सोचता था, और अमेरिका अपने हितों के लिए भारतीय जलक्षेत्र के पास भी अस्थिरता पैदा करने से नहीं हिचकिचाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र पहले से ही अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। यहाँ समुद्री संतुलन के लिए भारत पर अपनी नौसैनिक निगरानी और समुद्री डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने का दबाव होगा। अंडमान-निकोबार कमांड और पश्चिमी नौसेना कमान की गतिविधियाँ तेज करनी पड़ सकती हैं। भारत लंबे समय सेरणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता आया है। लेकिन अमेरिका ने कार्रवाई भारतीय सीमा के अत्यंत निकट की है, तो भारत के सामने दो विकल्प हैं - सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देना या चुप रहना –दोनों का अलग संदेश जाएगा। भारत को यह तय करना होगा कि अमेरिकी नौसेना nited States Na14 की कार्रवाई को मौन समर्थन tacit support देता है या तटस्थ रहता है। यह आलेख लिखे जाने तक भारत सरकार ने IRIS Dena के डूबने पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है जिसमें उसने सीधे-सीधे जांच, आरोप, या निंदा का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया हो। बीते दशक में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्षेत्रीय गठबंधनों ने हिंद महासागर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना दिया है। यदि अब यहाँ प्रत्यक्ष सैन्य टकराव होने लगें, तो यह क्षेत्र स्थायी अस्थिरता का शिकार हो सकता है। भारत के लिए, यह स्थिति अत्यंत जटिल है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही वैश्विक अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में हिंद महासागर में सैन्य तनाव का विस्तार दीर्घकालिक आर्थिक अनिश्चितता पैदा कर सकता है। वह न तो अमेरिका से दूरी बना सकता है, न ही ईरान जैसे क्षेत्रीय साझेदारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है। यदि हिंद महासागर अब महाशक्तियों की प्रत्यक्ष भिड़ंत का अखाड़ा बनने की ओर बढ़ रहा है तो भारत की भूमिका क्या होगी–मूक दर्शक या निर्णायक शक्ति? ईरान का युद्धपोत, जो भारत के निमंत्रण पर आया था, भारत की समुद्री सीमा के निकट डुबोया गया है, तो तेहरान यह अपेक्षा करेगा कि भारत कम से कम सिद्धांततः इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दे। संप्रभुता केवल भूमि की सीमा तक सीमित नहीं होती; समुद्री सीमाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि भारत इस पर स्पष्ट रुख नहीं लेता, तो भविष्य में अन्य शक्तियाँ भी इसी प्रकार की कार्रवाई को सामान्य मान सकती हैं। यह घटना केवल एक युद्धपोत के डूबने की नहीं है; यह भारत की सामरिक सोच की परीक्षा है। क्या भारत हिंद महासागर में अपने प्रभाव क्षेत्र की रक्षा के लिए स्पष्ट और साहसिक रुख अपनाएगा? रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ केवलकिसी के साथ न होना नहीं है। इसका अर्थ है– अपनी शर्तों पर निर्णय लेना, अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना, और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्ट संदेश देना। याद रहे कि चुप्पी साधना भी एक प्रकार का संदेश होता है–और कई बार वह शब्दों से अधिक मुखर होता है। हिंद महासागर में बारूद की गंध केवल एक चेतावनी है। प्रश्न यह है–क्या भारत इसे समझेगा?

ईरान के साथ कौन-से देश हैं? यूएस-इजराइल के साथ कौन-से देश खड़े हैं, तटस्थ रुख वाले देशों के नाम क्या हैं?

मध्य-पूर्व में भड़का ईरान का युद्ध अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर देने वाला संकट बन चुका है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद वैश्विक राजनीति स्पष्ट रूप से तीन खेमों में बंटती दिखाई दे रही है। एक ओर वे देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, दूसरी ओर वे देश हैं जो अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई को समर्थन दे रहे हैं, जबकि तीसरा समूह उन देशों का है जो खुलकर किसी पक्ष में नहीं आ रहे और खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उन देशों की बात करें जो ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम रूस और चीन का है। इन दोनों देशों ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है और इसे क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाला कदम कहा है। रूस पहले से ही पश्चिमी देशों के साथ टकराव की स्थिति में है, इसलिए उसने ईरान के खिलाफ हमले की तीखी आलोचना की है और कूटनीतिक समर्थन दिया है। चीन ने भी संयम बरतने की अपील करते हुए यह स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए। इन महाशक्तियों के अलावा उत्तर कोरिया और वेनेजुएला जैसे देश भी ईरान के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। इसके साथ ही मध्य-पूर्व में कई ऐसे संगठन हैं जो ईरान के रणनीतिक सहयोगी माने जाते हैं, जैसे लेबनान का हिज्बुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही। ये समूह लंबे समय से अमेरिका और इजराइल के प्रभाव का विरोध करते रहे हैं और इस संघर्ष में भी ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे समूह को अक्सरप्रतिरोध धुरी कहा जाता है, जो पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश करता है। अब दूसरे खेमे की बात करें, जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। इस युद्ध के सबसे बड़े पक्षकार स्वयं अमेरिका और इजराइल हैं। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है, जबकि अमेरिका ने अपने सहयोगी की सुरक्षा का हवाला देकर सैन्य अभियान में भाग लिया है। इनके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी क्षेत्र के कुछ देश भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी रणनीति के करीब दिखाई देते हैं। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और ये देश लंबे समय से ईरान को क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखते रहे हैं। ईरान युद्ध के मुद्दे पर पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो का रुख भी दिलचस्प है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे ईरान की परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कमजोर करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि नाटो प्रमुख ने यह भी साफ किया कि नाटो स्वयं इस युद्ध में शामिल होने की कोई योजना नहीं बना रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो एक संगठन के रूप में इस संघर्ष में नहीं उतरेगा, लेकिन उसके कुछ सदस्य देश अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को अपने स्तर पर समर्थन दे सकते हैं। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि पश्चिमी गठबंधन के भीतर भी युद्ध को लेकर पूरी तरह एकमत स्थिति नहीं है। तीसरा समूह उन देशों का है जो खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समूह में भारत, कई यूरोपीय देश, ब्रिटेन, कतर, ओमान और कॉकेस क्षेत्र के कुछ देश शामिल हैं। इन देशों ने सीधे किसी पक्ष का समर्थन करने की बजाय युद्ध को रोकने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। भारत जैसे देश ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कदम उठा रहे हैं। वहीं कतर और ओमान जैसे देश मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच संवाद कराने में सक्रिय रहे हैं। इस पूरे संकट के बीच अमेरिका की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका जिस तरह से सैन्य कार्रवाई कर रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं की अनदेखी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर हिंद महासागर में ईरानी पोत को मार गिराने की घटना ने यह संकेत दिया कि यह संघर्ष केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक समुद्री मार्गों तक फैल सकता है। इसके अलावा जब स्पेन ने अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इंकार किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना कर दी। दूसरी ओर ब्रिटेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति तो दी, लेकिन कई शर्तों के साथ, जिससे ट्रंप स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं दिखाई देते। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों से लगभग बिना शर्त समर्थन की उम्मीद कर रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। विडंबना यह है कि ट्रंप एक तरफ यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रुकवाया है और इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने गाजा के लिएबोर्ड ऑफ पीस जैसी पहल भी की। लेकिन दूसरी ओर ईरान के खिलाफ युद्ध को जिस तरह आगे बढ़ाया गया है, उसने पूरी दुनिया को अस्थिरता और युद्ध की आशंका से भर दिया है। आलोचकों का कहना है कि शांति की बात करने के साथ-साथ युद्ध की आग को भड़काना गहरे राजनीतिक विरोधाभास को दर्शाता है। इसके अलावा, इस युद्ध ने विश्व राजनीति में गहरे बदलाव पैदा कर दिए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि दुनिया फिर से बड़े शक्ति-गठबंधनों में बंटती दिखाई दे रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ हैं, जबकि रूस और चीन जैसे देश दूसरी ओर खड़े दिखाई देते हैं। यह स्थिति एक नई महाशक्ति प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा करती है। दूसरा बड़ा परिवर्तन मध्य-पूर्व की राजनीति में देखने को मिल रहा है।

कई अरब देशों और इजराइल के बीच सुरक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वे ईरान को अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। इससे क्षेत्र में नए सैन्य और राजनीतिक गठबंधन बन रहे हैं। तीसरा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और फारस की खाड़ी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। युद्ध के कारण तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। बहरहाल, ईरान का यह युद्ध केवल मिसाइलों और बमों का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन की लड़ाई भी बन चुका है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैचहाना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00862)

इमरान प्रतापगढ़ी के आवास पर हुआ रोज़ा इफ़्तार का एहतेमाम

आपसी भाईचारा व अमन सलामती की हुई दुआ

मुरादाबाद। दीन ए इस्लाम के सबसे ज्यादा अफ़ज़ल और बरकत वाले माह रमज़ान उल मुबारक में साम्प्रदायिक सौहार्द व आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के मकसद से रोज़ा इफ्तार का सिलसिला जारी है।इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग एवं रा'यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के नई दिल्ली स्थित आवास पर रोज़ा इफ़्तार का एहतेमाम किया गया। इस मुबारक मौके पर श्री प्रतापगढ़ी ने कहा कि रमज़ान का पाक महीना हमें मोहब्बत, भाईचारे, सब्र और इंसानियत का पैग़ाम देता है। इफ़्तार की इस रूहानी महफ़िल में मुल्क की तरक्क़ी, आपसी सौहार्द और समाज में एकता को मजबूत करने पर भी सार्थक चर्चा हुई।दुआ की गई कि अल्लाह तआला हम सबकी इबादतों को क़ुबूल फरमाए और हमारे देश में अमन, भाईचारा और तरक्क़ी हमेशा कायम रखे। इफ्तार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुरादाबाद निवासी मुहम्मद अहमद खान समेत बड़ी संख्या ने पार्टी पदाधिकारियों और आम रोजदारों ने शिरकत की।

रमज़ान के तीसरे जुमे पर मस्जिदों में उमड़ी रोज़दारों की भीड़

मुरादाबाद।

रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे पर शहर की मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोजेदार नमाज़ अदा करने पहुंचे।

जामा मस्जिद सहित शहर की प्रमुख मस्जिदों में जुमे की नमाज के लिए सुबह से ही तैयारियां की गईं और नमाज के बाद अल्लाह से मुल्क में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई।

जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले नायब शहर इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली ने रमजान की फजीलत, रोजे की अहमियत बताते हुए नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी।

उन्होंने कहा कि माहे मुबारक का दूसरा अशरा अन्तिम दौर में है और तीसरे अशरे की शुरूआत होने जा रही है। ऐसे में हमे इबादत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। नमाज के बाद लोगों ने रोज़ा, इबादत और नेक अमल की दुआ करते हुए एक-दूसरे को जुमा

मुल्क में अमन-चैन और खुशहाली की मांगी दुआ

मुबारक भी बोला। जामा मस्जिद के साथ ही शहर की लाल मस्जिद, कुईयां वाली मस्जिद, तख्त वाली मस्जिद, मौलसिरी मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। रमजान के दूसरे अशरे की अहमियत को देखते हुए लोग इबादत में अधिक समय गुजार रहे हैं। उलेमाओं के अनुसार तीसरे अशरे में इबादत का सवाब 'यादा होता है और इसी दौरान शब-ए-कद्र की मुबारक रात भी आती है। प्रशासन की ओर से भी जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। जामा मस्जिद क्षेत्र में फोर्स तैनात रही। अन्य मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा ताकि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर

मुरादाबाद। दलपतपुर-डूंगरपुर रोड पर गुरूवार को तेज रफ्तार कार की टकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उनकी सात वर्षीय बेटी भी घायल हो गई। मूंढापाण्डे थाना क्षेत्र के ग्राम सीतापुर निवासी दिनेश (×0) बाइक से पत्नी क्रांति (28) और करीब सात वर्षीय बेटी वंशिका के साथ मूंढापांडे के ग्राम सिरसखेड़ा में अपनी रिश्तेदारी में गये थे। जहां से वे गुरूवार को अपने घर वापस लौट रहे थे। परिजनों ने बताया गया कि जैसे ही वह दलपतपुर-डूंगरपुर रोड पर राजधानी ढाबे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही कार के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।हादसे में दिनेश और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भोजपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया, वहीं क्रांति की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल मुरादाबाद रेफर कर दिया गया,वहीं बेटी वंशिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर में मृतक दिनेश के भाई गौतम कुमार ने कार चालक के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी, जिसके पर भगतपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

हाईकोर्ट प्रयागराज की अधिवक्ता ने कहा- न्याय व्यवस्था का मूल आधार है समानता और निष्पक्षता

फतेहपुर।

महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने के लिए नये-नये नियम और कानून बनने के बावजूद महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ पा रही है।

क्या पीड़ित महिला की जाति-धर्म या वर्ग देखकर जाँच और कार्रवाई की जाति है ?

इस पर हाईकोर्ट प्रयागराज की अधिवक्ता माहीनम हारून ने कहा कि महिलाओं से जुड़े किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न के मामलों में कार्यवाही पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था का मूल आधार समानता और निष्पक्षता है। इसलिए किसी भी पीड़िता के साथ उसकी जाति, धर्म, वर्ग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किया जाना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानून और

संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। कहा कि उनका स्पष्ट मत है कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं।

इसलिए महिलाओं के मामलों में जांच और कार्रवाई केवल तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों के आधार पर की जानी चाहिए। प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों का दायित्व है कि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के त्वरित एवं प्रभावी कदम उठाएं, ताकि पीड़िताओं को समय पर न्याय और

कानून और संविधान की भावना के विरुद्ध है भेदभाव महिलाओं के मामलों में तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों के आधार पर हो कार्रवाई अपील-महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण या पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति का समाज के सभी वर्ग करें विरोध

सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों से भी अपेक्षा है कि वे महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहें तथा किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण या पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति का विरोध करें।

जिले में तंबाकू उत्पादों की बढ़ती कीमतें- आखिर जिम्मेदार कौन?

बहराइच।

शहर और नानपारा समेत सभी तहसीलों व कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि कई दुकानदार एमआरपी से यादा कीमत पर खुलेआम बिक्री कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे और ग्रामीण इलाकों में गुटखा-पान मसाला धड़ल्ले से महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। कई जगहों पर 5 और 10 रुपये वाले पाउच 7 से 12 रुपये तक में बिकने की शिकायत सामने आ रही है। बाजार में बिकने वाला सिस्टम गुटखा 10 का 4 मिलता था अब 12 का 3 मिल रहा है कमला

पसंद गुटखा 5 का एक मिलता था अब 7 का एक मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग की अनदेखी या मिलीभगत के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अगर समय-समय पर जांच और कार्रवाई होती, तो शायद दुकानदारों की यह मनमानी नहीं चल पाती। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और गंभीर बताई जा रही है। वहां न तो कीमतों की निगरानी हो रही है और न ही कोई सख्त कार्रवाई, जिससे दुकानदार अपनी मर्जी से दाम बढ़ाकर बेच रहे है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि तंबाकू उत्पादों की एमआरपी की सख्ती से जांच की जाए। बाजार में मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित किया जाये। क्या प्रशासन इस महंगाई पर लगाम लगाएगा, या फिर गुटखा-पान मसाले की मनमानी कीमतें यूं ही बढ़ती रहेंगी?

इन्सपायर अवार्ड मानक योजना में जनपद के रिकॉर्ड 146 आईडिया चयनित

मुरादाबाद। नवाचारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना इन्सपायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश के विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ नवाचारी आईडिया का चयन किया जाता है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में इस योजना के प्रारम्भ से अभी तक रिकॉर्ड 146 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इन्सपायर अवार्ड मानक योजना की जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी बबिता मेहरोत्रा ने बताया कि इस योजना के राजय स्तरीय नोडल अधिकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक विवेक नौटियाल, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद देवेंद्र कुमार पांडेय, सह जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार के निर्देशन में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने आईडिया ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार को भेजे थे। जिसमें से जनपद के बेसिक विभाग के जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं पब्लिक स्कूल के रिकॉर्ड 146 विद्यार्थियों का चयन किया गया है । इस उपलब्धि पर जनपद मुरादाबाद पूरे प्रदेश में नवें स्थान पर आया है। नोडल ने बताया कि इन विद्यार्थियों को नवाचारी मॉडल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खाते में दस हजार रुपये की धनराशि भेजी जाएगी जिनसे विद्यार्थी अपने आईडिया को मॉडल का मूर्त रूप प्रदान करेंगे। उसके बाद जनपद स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाएगा उनमें से चयनित मॉडलों को रा'य स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रधानाचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी, नोडल शिक्षकों व चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उ"वल भविष्य की कामना की और कहा कि इस प्रकार की योजनाएं ब'चों में वैज्ञानिक सोच रचनात्मकता, सृजनशीलता का विकास करती है।

मेजा में दिनदहाड़े किशोरी का अपहरण, परिजनों ने हाईवे किया जाम

मेजा,प्रयागराज।

जनपद प्रयागराज यमुनापार के मेजा में शुक्रवार दोपहर 12 बजे दिनदहाड़े स्कार्पियो सवार बदमाशों ने इंटर की छात्रा का अपहरण कर लिया। छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ ऊंचडीह बस स्टॉप बाजार से मार्केट कर पैदल घर लौट रही थी। छोटी बहन रोती रही लेकिन बेखौफ बदमाश इंटर की छात्रा को जबरी अपनी गाड़ी में बैठा कर भाग गए।

घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो ग्रामीण संग वह सड़क पर आ गए। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर चक्का जाम कर बेटी की बरामदगी और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। मौके पर मेजा के एसीपी संत प्रसाद उपाध्याय के साथ मेजा और मांडा पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुट गई। मांडा थाना क्षेत्र के लक्षन चौकठा गांव के सूर्य नारायण यादव गांव के समीप ही बिल्डिंग की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार दोपहर में उनकी बड़ी बेटी इंटर की छात्रा पुष्पा यादव (17) अपनी छोटी बहन रूपा यादव (13)

के साथ ऊंचडीह बस स्टॉप बाजार करने गई थी। दोनों बहनें पैदल ही घर लौट रही थीं कि जैसे हाईवे पर भरारी गांव के सामने पहुंची वैसे ही पीछे से तेज स्पीड में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ खड़ी हुई। स्कॉर्पियो से नीचे उतरे दो लोगों ने पुष्पा यादव को जबरन खींचकर स्कॉर्पियो में बैठा लिया और भाग निकले।

*दिन दहाड़े हुई वारदात से

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

यह सब देख छोटी बेटी बहन रूपा यादव रोती चिल्लाती रही लेकिन बेखौफ बदमाश उसे लेकर मांडा की तरफ भाग गए। इसकी सूचना परिजनों को हुई तो वह ग्रामीणों संग सड़क पर आ गए। आक्रोशित परिजनों ने लक्षन चौकठा गांव के सामने हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पर मेजा के एसीपी संत प्रसाद

मेजा,मांडा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा लड़की को किया सकुशल बरामद

उपाध्याय मेजा थाने के इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह और मांडा इंस्पेक्टर के साथ मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुट गए।

परिजनों की मांग है कि बेटी की बरामदगी के साथ बदमाश तत्काल गिरफ्तार किए जाएं। घटना को लेकर मां का रो-रो कर बुरा हाल है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्रीय विधायक संदीप पटेल मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी पर पहुंची मेजा मांडा पुलिस व एसओजी टीम टीम ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए अपहृत लड़की को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। मेजा मात्रा व एस ओ जी टीम अपहरणकर्ता की तलाश तेज कर दी है।

राधास्वामी सत्संग को लेकर इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में स्थित राधास्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स में 6 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले राधास्वामी सत्संग ब्यास के बड़े धार्मिक कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इस कार्यक्रम में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है. इसी चलते कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा और कुछ जगहों पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रोक भी लगाई जाएगी, ताकि भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था बनी रहे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक राधास्वामी सत्संग ब्यास का यह कार्यक्रम 6 मार्च से 8 मार्च तक छतरपुर क्षेत्र के भाटी माइंस स्थित राधास्वामी सत्संग परिसर में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. अनुमान है कि इनमें से करीब 80 हजार श्रद्धालु रात के समय भी परिसर में ठहर सकते हैं. श्रद्धालुओं का आना 6 मार्च की सुबह करीब 5 बजे से शुरू होने की उम्मीद है. बड़ी संख्या में लोगों के आने को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है, ताकि आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति न बने. कार्यक्रम के दौरान भाटी माइंस इलाके में वाहनों की संख्या अचानक बढ़ने की संभावना है. इसके कारण छतरपुर रोड (एसएसएन मार्ग), भाटी माइंस रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड और मंडी रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर संभव हो तो इन मार्गों पर यात्रा करने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर जांच लें. साथ ही जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सत्संग परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं और उनके वाहनों की एंट्री मुख्य रूप से भाटी माइंस रोड से कराई जाएगी. कार्यक्रम आयोजकों ने अलग-अलग प्रकार के वाहनों और आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश व्यवस्था भी तैयार की है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे सुबह 5 बजे से पहले ही पहुंचने की कोशिश करें, ताकि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में ज्यादा समय न लगे. फरीदाबाद और गुरुग्राम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खास रूट तय किया है. इन इलाकों से आने वाले लोगों को डेरा बॉर्डर के रास्ते भाटी माइंस स्थित सत्संग परिसर तक पहुंचने की सलाह दी गई है. पुलिस का कहना है कि इस मार्ग का उपयोग करने से रास्ते में लगने वाले ट्रैफिक जाम से काफी हद तक बचा जा सकेगा और श्रद्धालु आसानी से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकेंगे. कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 6 मार्च से 8 मार्च तक रोजाना सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.

कोई समझौता नहीं होगा, ट्रंप ने किया साफ, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, इसी में उसकी भलाई

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान पर अपना रुख और कड़ा कर दिया। ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले लगातार जारी है तथा इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में इजराइल एवं अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखे है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों में मारे गए अयातुल्ला अली खामेनेई के स्थान पर उनके बेटे मोजतबा खामेनेई का सर्वोच्च नेता के तौर पर चयन अस्वीकार्य होगा। ईरान और अमेरिका-इजराइल गठबंधन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, मध्य पूर्व में लगातार सातवें दिन भी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव जारी है और तनाव कम होने के कोई तत्काल संकेत नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले छह दिनों में ईरान में इस युद्ध में मरने वालों की संख्या 1,200 से अधिक हो गई है, लेबनान में 70 से अधिक और इजराइल में लगभग एक दर्जन लोग मारे गए हैं। युद्ध हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे मध्य पूर्व और उससे बाहर के 14 और देश प्रभावित हो रहे हैं। ईरान द्वारा कुवैत पर किए गए जवाबी हमलों के बाद अमेरिकी दूतावास बंद हो गया है, और ईरान में युद्ध बढ़ने के साथ ही पूरी तरह से काम बंद करने वाला यह दूसरा अमेरिकी राजनयिक मिशन बन गया है। कुवैत वह स्थान भी है जहां रविवार को एक ईरानी ड्रोन हमले में छह अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कुछ देशों ने मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए- हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर भी हमें अपने राष्ट्र की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने में कोई संकोच नहीं है। मध्यस्थता में उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने ईरानी जनता को कम आंका और इस संघर्ष को भड़काया। अजरबैजान ने ईरान पर ड्रोन हमले करने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था जिसे तेहरान ने खारिज कर दिया। ईरान ने बृहस्पतिवार सुबह इजराइल और अमेरिका के कई अड्डों पर नये सिरे से हमले किए और धमकी दी कि हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को टॉरपीडो के हमले से डुबोने के लिए अमेरिका को बहुत पछताना पड़ेगा। ईरान समर्थक हिजबुल्ला लड़ाकों के साथ संघर्ष बढ़ने के बीच इजराइल ने चेतावनी जारी कर बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के लिए बड़े पैमाने पर निकासी का परामर्श जारी किया।

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों ने इजराइली सैनिकों की और टुकड़ियों के सीमा पार जाने के बीच दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई की सूचना दी। इस बीच, पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमता, नेतृत्व और परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया है। ईरान ने जवाबी हमले करते हुए अरब में अपने पड़ोसियों को निशाना बनाया है। इन हमलों के कारण तेल आपूर्ति बाधित हो गई है और वैश्विक हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। संबंधित देशों के अधिकारियों के अनुसार, इस युद्ध में ईरान में कम से कम 1,230 लोग, लेबनान में 120 से अधिक लोग और इजराइल में लगभग एक दर्जन लोग मारे गए हैं। हमलों में छह अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं।

पेजेशकियन बोले- हमें कम ने आंकें

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका और इसराइल से झगड़े में कुछ देशों ने बीच-बचाव की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, हम भी शांति पसंद करते हैं, लेकिन अपनी सम्मान और स्वतंत्रता के साथ। हमने पिछले अपने हफ्ते सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को खो दिया। शायद कुछ लोगों ने हमें कम आंक लिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कुछ देशों ने बीच-बचाव की कोशिशें शुरू कर दी हैं। स्पष्ट कर दूं कि हम इस इलाके में हमेशा शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने देश के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे।

इजरायल-यूएस और ईरान की जंग पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेताया

भारत को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी

नई दिल्ली । मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की कीमत भारत को भी चुकानी पड़ेगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि इस जंग की वजह से भारत में ईंधन महंगा हो जाएगा और आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा. राहुल गांधी ने कहा, सीधे तौर पर यह युद्ध अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच नजर आ रहा है लेकिन हकीकत में यह अमेरिका, चीन और रूस के बीच में एक व्यापारिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को दिखाता है. राहुल ने कहा, अमेरिका वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि चीन लगातार आगे बढ़ रहा है और अंतर को कम कर रहा है. राहुल गांधी ने कहा, मिडिल ईस्ट एनर्जी प्रोडक्शन में दुनिया का बड़ा केंद्र है, अब इस आपूर्ति पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा, होर्मुज ऑफ स्ट्रेट दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण रूट है. तनाव बढ़ने की वजह से इसके परिणाम इस क्षेत्र से कहीं ज्यादा दूर तक महसूस किए जाएंगे. राहुल गांधी ने कहा, जब ये शक्तियां आपस में लड़ रही हैं तो अन्य देशों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी. खास तौर से भारत पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो मध्य पूर्व से ऊर्जा आयात पर अपनी भारी निर्भरता रखता है.

कांग्रेस नेता ने बताया शक्ति और बल में अंतर

विपक्ष के नेता ने कहा, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के संघर्ष से मुझे अहसास हुआ कि शक्ति और बल में अंतर होता है। उन्होंने आगे कहा, ब्रिटिश शासन के पास बल तो था, पर सत्ता नहीं। गांधीजी के पास बल नहीं था, पर सत्य था, इसलिए उनके पास शक्ति थी। इसी तरह नारायण गुरुजी के पास बल नहीं था। उनके पास अपार धन-दौलत नहीं थी। वह आलीशान वाहन में नहीं घूमते थे। फिर भी वह अपने समय में केरल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने आगे कहा, कल्पना कीजिए कि सौ साल बाद केरल का पूरा राजनीतिक वर्ग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के एकत्र हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी और नारायण गुरु ने हिंसा और नफरत का इस्तेमाल करने वालों को यह संदेश दिया कि इससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है।

रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी मंजूरी- संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा; विपक्षी नेताओं ने भी दागे तीखे सवाल

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीद के मामले में भारत को एक महीने की मोहलत दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस मुद्दे को भारत की विदेश नीति और राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कहा है कि किसी भी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि भारत कब और कितना तेल खरीदे। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा, यह बात समझ से परे है कि कोई दूसरा देश भारत को इस तरह परमिशन दे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी अनुमति आमतौर पर एक ताकतवर देश अपने अधीन या कमजोर देश को देता है। अगर भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए एक महीने की छूट दी गई है, तो इसका मतलब है कि हमारी विदेश नीति कहीं न कहीं दूसरे देश के इशारों पर चल रही है। उन्होंने इसे भारत की राजनीतिक स्वायत्तता के लिए एक चिंताजनक संकेत बताया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

नई दिल्ली । संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) के आधार पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने मेरिट के आधार पर कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। इस बार अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम है। वहीं, तीसरा स्थान एकांश ढुल ने हासिल किया है। लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित हुई थी, जबकि इंटरव्यू दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच लिए गए। चयनित उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा , भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप A और 'B') में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। आयोग ने बताया कि 348 उम्मीदवारों का चयन फिलहाल प्रोविजनल (अस्थायी) रखा गया है। इन उम्मीदवारों के दस्तावेजों और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के सत्यापन के बाद ही उनके चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं, दो उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। आयोग ने इन उम्मीदवारों के परिणाम को कुछ कारणों से फिलहाल जारी नहीं किया है। उम्मीदवारों के अंक परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। सरकार द्वारा कुल 1087 पदों पर भर्ती की सूचना दी गई है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 180 पद, भारतीय विदेश सेवा के लिए 55 पद, और भारतीय पुलिस सेवा के लिए 150 पद निर्धारित किए गए हैं।

रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी छूट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा - यह भारत की संप्रभुता पर हमला है

नई दिल्ली । रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका द्वारा भारत को दी गई 30 दिनों की अस्थायी छूट पर देश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने इसे भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला करार देते हुए केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी से बात करते हुए जयराम रमेश ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की घोषणा को अत्यधिक आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा, यह हमारी संप्रभुता का मुद्दा है। हमारी सरकार को यह तय करना चाहिए कि हम कहां से, कब और कितना तेल खरीदेंगे। अमेरिका हमें सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और तेल मंत्री चुप क्यों हैं? जयराम रमेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में जोर-शोर से उठाएगी। उन्होंने वाशिंगटन से आने वाली घोषणाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा, हमें सारी जानकारी वाशिंगटन से क्यों मिल रही है? चाहे रूसी तेल की बात हो या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की, पहली घोषणा अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की जाती है। सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी चाहिए।

खतरे में है रणनीतिक स्वायत्तता - मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय संप्रभुता गंभीर खतरे में है। खड़गे ने लिखा, पीएम मोदी एपस्टीन फाइल्स और अडानी केस को लेकर ब्लैकमेल हो रहे हैं। अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदने के लिए अनुमति देना या छूट देना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार कूटनीतिक जमीन खो रही है। इस तरह की भाषा प्रतिबंधित देशों के लिए इस्तेमाल की जाती है, भारत जैसे समान भागीदार के लिए नहीं।

रेड कॉरिडोर का सपना देखने वाले हो जाएंगे नाकाम- अमित शाह

नई दिल्ली । गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश को 31 मार्च तक नक्सलवाद से मुक्त बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल उन लोगों के मंसूबों को विफल कर देंगे जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक तथाकथित रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देख रहे हैं। ओडिशा के कटक जिले के मुंडाली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सुरक्षा बल उन ताकतों को हराएंगे, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लेकर नेपाल के पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है और अब देश लाल आतंक को समाप्त करने के करीब पहुंच गया है। शाह ने सीआईएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह बल देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षा देकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने देश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी प्रगति की है।

बीजेपी ने 9-10 मार्च को अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली । संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह प्रस्ताव नियमों और परंपराओं के अनुसार है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी विपक्षी दलों ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस पर 9 मार्च को चर्चा होगी। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि इस नोटिस पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जयराम रमेश ने कहा, यह एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमने जो प्रस्ताव दिया है, वह नियमों और परंपराओं के मुताबिक है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। उदाहरण के लिए, 1954 में महान स्पीकर जी वी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।

कांग्रेस ने कहा- प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, ये संसदीय लोकतंत्र के साधन हैं। विपक्ष को इसका पूरा अधिकार है। इस पर बहस होगी, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने स्पीकर के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के खास उदाहरण दिए हैं, जबकि विपक्षी सदस्यों पर झूठे आरोप लगाए गए। हमने पूरा संदर्भ बताया है और इस पर बहस होनी चाहिए।

क्या है स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया

अगले सोमवार को लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दौरान वह अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वह सदस्यों के बीच बैठेंगे। नियमों के अनुसार, बिरला को सदन में अपनी बात रखने और अपना बचाव करने का पूरा अधिकार होगा। वह प्रस्ताव के खिलाफ वोट भी दे सकते हैं। संविधान विशेषज्ञ पी डी टी आचार्य के अनुसार, जब प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। वह सत्ता पक्ष की सीटों पर बैठेंगे। असल में, जिस दिन यह नोटिस दिया गया था, उसी दिन से बिरला ने सदन की अध्यक्षता करना बंद कर दिया था।

क्यों दिया गया नोटिस?

लगभग 118 विपक्षी सदस्यों ने यह नोटिस दिया है। उनका आरोप है कि स्पीकर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा, आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया था। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, के सुरेश और मोहम्मद जावेद ने यह नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा था। संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। हालांकि, उन्हें सदन में बोलने और अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास करके स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है।

भाजपा-चुनाव आयोग की साजिश को करूंगी बेनकाब, एसआईआरके खिलाफ धरना शुरू करते हुए बोली ममता बनर्जी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची से कथित तौर पर मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने के विरोध में एक धरना शुरू किया। इस कदम से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और चुनाव आयोग के बीच टकराव और बढ़ गया है। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरना शुरू करते हुए, बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें बेनकाब करने की कसम खाई। टीएमसी सुप्रीमो ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में कहा, मैं बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की भाजपा-चुनाव आयोग की साजिश को बेनकाब करूंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित मतदाता सूची में कई मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया है। बनर्जी ने कहा, मैं उन मतदाताओं को, जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, इस विरोध स्थल पर प्रस्तुत करूंगी। यह धरना, जो मध्य कोलकाता में दोपहर 2:15 बजे शुरू हुआ। इसकी घोषणा टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने चुनाव आयोग पर राजनीतिक रूप से प्रेरित अभ्यास करने का आरोप लगाया था, जिससे लाखों योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। यह विवाद चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट आने के बाद बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर से एसआईआर शुरू होने के बाद से 63.66 लाख नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 8.3 प्रतिशत है। इसके कारण बंगाल में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गई है। इसके अलावा, 60.06 लाख से अधिक मतदाताओं को जांच के दायरे में रखा गया है। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में कानूनी जांच के माध्यम से उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी। यह प्रक्रिया निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों को और भी बदल सकती है।

राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट के बीच समुद्र में भारतीय नेतृत्व का आह्वान किया

नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का जिक्र करते हुए शुक्रवार को कहा कि बदलती भू-राजनीति के इस दौर में महासागर एक बार फिर दुनिया के शक्ति संतुलन के केंद्र में आ गए हैं और भारत की जिम्मेदारी है कि वह आत्मविश्वास एवं क्षमता के साथ नेतृत्व प्रदान करे। सिंह ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम बेहद असामान्य हैं और क्षेत्र की स्थिति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया में जो हो रहा है, वह बेहद असामान्य है। इस समय इस पर कोई ठोस टिप्पणी करना कठिन है कि पश्चिम एशिया में परिस्थितियां आगे किस दिशा में जाएंगी। उन्होंने कहा, यदि हम होर्मुज जलडमरूमध्य या फारस की खाड़ी के पूरे क्षेत्र को देखें तो यह दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में अशांति या व्यवधान होता है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। उन्होंने कहा, आज हम केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान देख रहे हैं। इन अनिश्चितताओं का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। सिंह ने कहा कि मौजूदा स्थिति ने महासागरों के महत्व को एक बार फिर रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, बदलती वैश्विक भू-राजनीति के इस दौर में महासागर एक बार फिर दुनिया के शक्ति संतुलन के केंद्र में आ गए हैं। ऐसे समय में एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की जिम्मेदारी है कि वह आत्मविश्वास, क्षमता और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ नेतृत्व प्रदान करे। रक्षा मंत्री ने हालांकि दो दिन पहले श्रीलंका के तट के पास अमेरिका द्वारा एक ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने की घटना का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिक्र नहीं किया।